



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १४ मई, १९८८/२४ वैशाख, १९१०

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, २० अप्रैल, १९८८

संख्या एफ० डी० एस० ए० (३)-४/८२-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ (१९८६ का ६८) की धारा ३० की उप-धारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग-I

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, १९८८ है।

(२) ये नियम १-५-१९८८ से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से उपभोक्ता संरक्षण (1986 का 68) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है।
- (ख) “अभिकर्ता” से पक्षकार की ओर से जिला फोरम या राज्य के समक्ष परिवाद अपील या जवाब प्रस्तुत करने के लिए यथास्थिति उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ग) “अपीलकर्ता” से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जो जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील करता है ;
- (घ) “ज्ञापन” से अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील का कोई ज्ञापन अभिप्रेत है ;
- (ङ) “विरোধी पक्षकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिवाद या दावे का उत्तर देता है ;
- (च) “प्रधान” से यथास्थिति जिला फोरम या राज्य आयोग का प्रधान अभिप्रेत है ;
- (छ) “प्रत्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपील के किसी ज्ञापन का उत्तर देता है ;
- (ज) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

2. शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

भाग-II

जिला फोरम

3. जिला फोरम के बैठने का स्थान.—जिला फोरम का कार्यालय जिला के मुख्यालय में स्थित होगा और जहां सरकार एक से अधिक जिलों में अधिकारिता रखने वाले, केवल एक ही जिला फोरम स्थापित करने का दिनिश्चय करनी है वहां वह ऐसे स्थापित जिला फोरम के स्थान और उसकी अधिकारिता को अधिसूचित करेगी।

4. जिला फोरम के कार्य-दिवस और उसका कार्यालय समय.—जिला फोरम के कार्य-दिवस और उसका कार्यालय समय वैसा ही होगा, जो राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए है।

5. मोहर और एमब्लम.—जिला फोरम की शासकीय मोहर और एमब्लम ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

6. जिला फोरम की बैठक.—जिला फोरम की बैठक जब कभी आवश्यक हो, प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी और शिकायत को शीघ्र निपटाने के हित में ऐसी बैठकें अपनी अधिकारिता में वह, किसी भी स्थान पर बुला सकेगा।

7. जिला फोरम के कर्मचारी.—राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो जिला फोरम के दिन, प्रतिदिन के कार्य में सहयोग देने और प्रधान द्वारा यथा सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन की पूर्ति राज्य सरकार की संचित निधि में से की जाएगी।

प्रयाजन के लिए ऐसे नियुक्त कर्मचारियों के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की जाएं।

8. प्रधान और जिला फोरम के सदस्यों के वेतन मान देय तथा अन्य भत्ते.—(i) जहां जिला फोरम का प्रधान, जिला न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो, जिला न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में प्राप्त होने वाली सभी प्रसुधाविएं प्राप्त करेगा। जहां प्रधान जिला न्यायालय का आसीन न्यायाधीश न हो, वहां वह जिला न्यायाधीश को देय वेतन का हकदार होगा किन्तु यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो तो सेवा निवृत्त व्यक्ति की पेंशन और वेतन उस द्वारा आहरण किए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो तो 150/- रु० प्रतिदिन मानदेय से अधिक नहीं होगा। अन्य सदस्य, यदि वे पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए हों तो वे 1,250/- रु० प्रतिदिन, संचित मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे या यदि वे अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए गए हों तो वे प्रत्येक बैठक के लिए 100/- रु० प्रतिदिन मान देय के रूप में प्राप्त करेंगे।

(ii) जिला फोरम का प्रधान और उसके सदस्य, सरकारी दौरे पर ऐसी दूरों पर ही यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के उच्चतम ग्रेड-I अधिकारी को प्राप्त है।

(iii) मानदेय या वेतन यथा स्थिति और अन्य भत्तों की पूर्ति राज्य सरकार की संचित निधि में से की जाएगी।

9. (i) जिला फोरम के प्रधान और सदस्यों की सेवाओं के निबन्धन और शर्तें.—नियुक्ति से पूर्व, जिला फोरम का प्रधान और उस का कोई सदस्य अपने आपको बचनबद्ध करेगा कि वह जिला फोरम में कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है या नहीं रखेगा, जिससे उसके प्रधान या सदस्य के रूप में किए जाने वाले कृत्यों पर, यथास्थिति प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(ii) प्रधान और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तों में, उसकी पदावधि के दौरान उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) जिला फोरम के प्रधान या किसी अन्य सदस्य के पद त्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(iv) जिला फोरम का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल उसके प्रधान या सदस्यों में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होंगी।

(v) जिला फोरम के सदस्यों की राय में कोई मतभेद होने पर उनका बहुमत अभिभावी होगा और जिला फोरम की राय या आदेश बहुमत के रूप में अभिव्यक्त किए जाएंगे।

(vi) प्रधान या कोई सदस्य जो अपने पद पर न रहा हो पद पर न रहने की तारीख से वह अपनी पांच वर्ष की अवधि के दौरान, संगठन के प्रबन्ध या प्रशासन में या उससे सम्बन्धित जिसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही चल रही हो, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा।

10. कतिपय परिस्थितियों में जिला फोरम के प्रधान या सदस्यों का उनके पद से हटाया जाना.—राज्य सरकार यथास्थिति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान या सदस्य के पद से हटा सकेगी :—

(क) जो दिवालिया घोषित किया जा चुका हो; या

(ख) जो ऐसे अपराध से दोष सिद्ध किया जा चुका हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता का अपराध है; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक दृष्टि से प्रधान या सदस्य का कार्य करने में अशक्त हो गया हो; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर रखा हो, जिससे उसके द्वारा प्रधान या सदस्य के रूप में किए जाने वाले कृत्यों पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है कि उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित के विरुद्ध है :

परन्तु प्रधान या किसी सदस्य को, इस नियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर, सरकार द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, जांच किए बिना और यथास्थिति कथित आधारों पर दोषी पाए जाने के बिना, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

11. परिवाद की प्राप्ति पर प्रक्रिया.—(1) जहां विरोधी पक्षकार परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथनों को स्वीकार कर लेता है, वहां जिला फोरम परिवाद का विनिश्चय, मामले के गुणागुण और उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, के आधार पर करेगा।

(2) यदि धारा 13 के अधीन संक्षिप्त की गई कार्यवाहियों के दौरान जिला फोरम पक्षकारों की सुनवाई के लिए तारीख नियत करता है, तो परिवादी तथा विरोधी पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं का, जिला फोरम के समक्ष सुनवाई की नियत तारीख की या सुनवाई के लिए स्थगित अन्य तारीख को, उपस्थित होना आवश्यक होगा। जहां परिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी नियत तारीख को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां जिला फोरम अपने विवेकानुसार परिवाद को या तो ब्यवितक्रम के लिए खारिज कर सकेगा या उसे गुणागुण के आधार पर विनिश्चित कर सकेगा। जहां विरोधी पक्षकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सुनवाई की नियत तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां जिला फोरम परिवाद पर एक पक्षीय निर्णय दे सकेगा।

3. उप-नियम (2) के अधीन कार्रवाई करते समय, जिला फोरम ऐसे निबन्धनों पर, जैसे वह उचित समझे, कार्य-वाहियों के किसी प्रक्रम पर भी परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा, किन्तु जहां माल की बाबत परिवाद का विश्लेषण या परीक्षण किया जाना अपेक्षित न हो, विरोधी पक्षकार द्वारा प्राप्त किए गए नोटिस की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर, और जहां पर माल की बाबत इस का विश्लेषण या परीक्षण किया जाना अपेक्षित हो, पांच मास की अवधि के भीतर यथा सम्भव, परिवाद का विनिश्चय करेगा।

4. जिला फोरम के आदेश, जिला फोरम के सदस्यों द्वारा जिन से इस का गठन हुआ है, हस्ताक्षरित मुद्रांकित और दिनांकित होंगे, और इन्हें पक्षकारों को निःशुल्क सूचित किया जाएगा।

12. माल के विश्लेषण और परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -- (1) जिला फोरम यदि आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन, साफ आधानपत्रों में जिन पर ठीक रूप से अवरोधक (स्टापर) लगे हों, माल के एक से अधिक नमूनों का उपबन्ध करने के लिए परिवादी को निर्देश दे सकेगा।

2. ऐसे माल के नमूने प्राप्त करने पर, जिला फोरम इन्हें मोहर बन्द करेगा और आधानपत्रों पर लेबल लगाएगा जिन में निम्नलिखित जानकारी दर्शित की जाएगी :—

- (i) उपयुक्त प्रयोगशाला का नाम और पता जिस को नमूने विश्लेषण तथा परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे ;
- (ii) जिला फोरम का नाम और पता ;
- (iii) मामला (केस) संख्या ;
- (iv) जिला फोरम की मोहर।

(3) जिला फोरम द्वारा नमूनों, समुचित प्रयोगशाला को उसके प्रस्तुतीकरण की तारीख से 45 दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो जिला फोरम द्वारा मंजूर किया जाए, अभिकथित त्रुटि का प्रकृति की बाबत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाएगा।

भाग-III

राज्य आयोग

13. राज्य आयोग के प्रधान और सदस्यों का वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते :—(1) जहां राज्य आयोग का प्रधान उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो वहां वह उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को मिलने वाली सभी प्रसुविधाएं प्राप्त करेगा। जहां प्रधान उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश नहीं, वहां यदि वह पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो, सात हजार रुपये प्रति मास संचित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया हो 300 रुपये प्रतिदिन मानदेय के रूप में प्राप्त करेगा। यदि अन्य सदस्य पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए हों, एक हजार पांच सौ रुपये प्रति मास संचित मानदेय या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए गए हों तो दो सौ पचास रुपये प्रति दिन प्रत्येक बैठक के लिए संचित मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे। परन्तु सदस्य सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई पेंशन का हकदार होगा। किन्तु मानदेय और पेंशन उस द्वारा आहरण किए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

2. प्रधान और सदस्यगण अर्ध सुसज्जित आवास के हकदार होंगे।

3. यथास्थिति मानदेय या वेतन और अन्य भत्तों की पूर्ति राज्य सरकार की सचिव निधि में से की जाएगी।

14. राज्य आयोग के प्रधान और सदस्यों की सेवा, निबन्धन और शर्तें :—(1) राज्य आयोग की प्रधान और उसका कोई सदस्य नियुक्ति से पूर्व अपने आप को वचनबद्ध करेगा कि वह राज्य आयोग में कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है या नहीं रखेगा, जिससे उसके प्रधान या सदस्य के रूप में किए जाने वाले कृत्यों पर यथास्थिति प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) प्रधान और सदस्य दो वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे और पुनः नियुक्ति के लिए हकदार होंगे :

परन्तु कोई भी प्रधान या सदस्य 5 वर्ष की अवधि से अधिक 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् जो भी पूर्व हो, पद पर नहीं रहेगा।

(3) उप-नियम (2) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

(क) प्रधान या कोई सदस्य अपने हाथ से लिख कर और राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा ; और

(ख) इन नियमों के नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(4) प्रधान और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तों में, उसकी पदावधि के दौरान उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) राज्य आयोग प्रधान या उसके किसी सदस्य के पद त्याग या उप-नियम (3) के अधीन हटाए जाने के कारण या अन्यथा हुई आकस्मिक रिक्ति, नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(6) राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल उसके प्रधान या सदस्यों में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई दृष्टि होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

7. राज्य आयोग के सदस्यों की राय में कोई मतभेद होने पर उनका बहुमत अभिभावी होगा और राज्य आयोग की राय या आदेश बहुमत के रूप में अभिव्यक्त किए जाएंगे।

8. राज्य आयोग का प्रधान या कोई सदस्य जो अपने पद पर न रहा हो, वह पद पर रहने की तारीख से अपनी पांच वर्ष की अवधि के दौरान, संगठन के या उससे सम्बन्धित प्रबन्ध या प्रशासन में, जिस के विरुद्ध अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही चल रही हो, कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं करेगा।

15. कतिपय परिस्थितियों में राज्य आयोग के प्रधान या सदस्यों का उनके पद से हटाया जाना.— राज्य सरकार प्रधान या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी :—

(क) जो दिवालिया घोषित किया जा चुका हो; या

(ख) जो ऐसे अपराध से सिद्ध दोष किया जा चुका हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधनता का अपराध है; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक दृष्टि से प्रधान या सदस्य का कार्य करने में अशक्त हो गया हो; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर रखा हो, जिससे उसके द्वारा प्रधान या सदस्य के रूप में किए जाने वाले कृत्यों पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है कि उस का अपने पद पर बने रहना लोकहित के विरुद्ध है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस उप-नियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इन निम्न विनिर्दिष्ट करें, जांच किए बिना और यथास्थिति कथित आधारों पर दोषी पाए जाने के बिना, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

16. राज्य आयोग के कार्यालय का स्थान.—राज्य आयोग का कार्यालय, राज्य की राजधानी में स्थित होगा।

17. राज्य आयोग के कार्य-दिवस और कार्यालय समय.—राज्य आयोग के कार्यालय दिवस और उसका कार्यालय समय वैसा ही होगा, जो राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए है।

18. राज्य आयोग की मोहर और एम्ब्लम.— राज्य आयोग की शासकीय मोहर और एम्ब्लम ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

19. राज्य आयोग की बैठक:— राज्य आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी और परिवाद अथवा अपील की शीघ्र शीघ्र निपटाने के हित में, वह ऐसी बैठकें अपनी अधिकारिता में किसी भी स्थान पर बुला सकेगा।

20. राज्य आयोग के कर्मचारी:— राज्य आयोग ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जो राज्य आयोग के दिन प्रतिदिन के कार्य में सहयोग देने और प्रधान द्वारा दिये गए कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन की पूर्ति राज्य सरकार की संचित निधि में से की जाएगी।

21. राज्य आयोग द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया:— परिवाद जिसमें निम्नलिखित विशिष्टताएं अन्तर्विष्ट होंगी परिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके अभिकर्ता द्वारा राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा, या यह राज्य आयोग के नाम रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा:—

- (क) परिवाद का नाम, विवरण और पता;
- (ख) यथास्थिति विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का नाम; विवरण और पता जहां तक उस का पता लगाया जा सके;
- (ग) परिवाद से सम्बन्धित तथ्य और इस का उदभव कब और कहाँ हुआ;
- (घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज;
- (ङ) राहत जिस का कि परिवाद ने दावा किया है।

(2) राज्य आयोग, उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी परिवाद को निपटाने के लिए, जिला फोरम द्वारा प्राप्त परिवाद सम्बन्धी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) सुनवाई की तारीख या सुनवाई के लिए स्थगित अन्य तारीख को पक्षकारों या उसके अभिकर्ताओं का राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत होना, आवश्यक होगा। जहां परिवादी या उसका अभिकर्ता उस तारीखों को, राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयोग अपने विवेकानुसार या तो परिवाद को व्यक्तिगत रूप से कारण खारिज कर सकेगा या उस पर गुणगुण के आधार पर अपना निर्णय दे सकेगा। जहां विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयोग, परिवाद पर एक पक्षीय निर्णय दे सकेगा।

(4) राज्य आयोग, ऐसे निबन्धनों पर जैसे वह उचित समझे, कार्यवाहियों के किसी क्रम पर भी परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा, किन्तु जहां वस्तुओं को बावत परिवाद का विश्लेषण या परीक्षण किया जाना अपेक्षित न हो, वहां विरोधी पक्षकार द्वारा प्राप्त किए गए नोटिस की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, और जहां वस्तुओं को बावत इस का विश्लेषण या परीक्षण किया जाना अपेक्षित हो, पांच मास की अवधि के भीतर, यथा सम्भव परिवाद का विनिश्चय करेगा।

(5) यदि उप-नियम (3) के अधीन, संचालित कार्यवाहियों के उपरान्त राज्य आयोग का परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के बारे में समाधान हो जाता है, तो वह यथा स्थिति विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को उन्हें अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में उल्लिखित एक या उससे अधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देश करते हुए, आदेश जारी करेगा।

22. अपील की सुनवाई की प्रक्रिया:— (1) अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा ज्ञापन राज्य आयोग को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया जायगा, अथवा उस नाम रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दायर किया गया ज्ञापन आसानी से पढ़ा जाने वाला सम्भवतः टाईप किया हुआ होना चाहिए और उसमें सुस्पष्ट शीर्षक तथा वृत्तान्त के बिना अपील के आधार दर्शित किए, जाएंगे और ऐसे आधार क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक जापन के साथ जिला फोरम के ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रतीत लगाई जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और उसके साथ ऐसे दस्तावेज भी लगाए जाएंगे जिससे जापन में उल्लिखित आक्षेप के आधारों को समर्थन प्राप्त होता है।

(4) जब अपील अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि के पश्चात् की गई हो, तब जापन के साथ शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन-पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें वे तथ्य दर्शाए होंगे, जिन पर अपीलार्थी राज्य आयोग का समाधान कराने के लिए निर्भर करता है कि परिसीमा की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतुक है।

(5) अपीलार्थी कार्यालय के प्रयोग के लिए आयोग को जापन की चार प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(6) नियत तारीख को या सुनवाई के लिए स्थगित अन्य तारीख को, पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक होगा। यदि अपीलार्थी या उसका अभिकर्ता ऐसी नियत तारीख को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो राज्य आयोग अपने विवेकानुसार या तो अपील को खारिज कर सकेगा या उसका गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय रूप से विनिश्चय कर सकेगा। यदि प्रत्यार्थी या उसका अभिकर्ता ऐसी नियत तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो राज्य आयोग उसके विरुद्ध एक पक्षीय रूप में कार्रवाई करेगा और मामले के गुणागुण के आधार पर अपील का विनिश्चय करेगा।

(7) राज्य आयोग की स्वीकृति के बिना, ऐसे आधार या आक्षेप पेश नहीं करेगा जो जापन में नहीं दिए गए हैं, अपीलार्थी पेश नहीं करेगा और न ही उसे इन के समर्थन में सूना ही जाएगा, किन्तु राज्य आयोग अपील का विनिश्चय करते समय केवल जापन में किए गए आक्षेप के आधारों तक ही सीमित नहीं रहेगा।

परन्तु राज्य आयोग जापन में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न किन्हीं आधारों पर अपना विनिश्चय तब तक नहीं करेगा जब तक कि इन से प्रभावित होने वाले पक्षकार को इस निमित्त राज्य आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(8) राज्य आयोग ऐसे निबन्धनों पर जैसे वह उचित समझे, किसी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा, किन्तु साधारणतया ऐसा स्थगन एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा, और यथा सम्भव अपील का विनिश्चय प्रथम सुनवाई की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

(9) अपील पर राज्य आयोग का आदेश राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होगा और इस आदेश की सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जाएगी।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्ध,
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of Government notification No. F.D.S.A (3)-4/82-III, dated the 20th April, 1988, is hereby published in the Rajptra, Himachal Pradesh as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th April, 1988

No. FDS. A(3)-4/82-III.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Governor of Himachal Pradesh is

pleased to make the following rules, namely:—

PART-I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection Rules, 1988.

(2) These shall come into force *w.e.f.* 1-5-1988.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);
- (b) “agent” means a person duly authorised by a party to present any complaint, appeal or reply on its behalf before the District Forum or the State Commission, as the case may be;
- (c) “appellant” means a party which makes an appeal against the order of the District Forum;
- (d) “memorandum” means any memorandum of appeal filed by the appellant;
- (e) “opposite party” means a person who answers complaints or claims;
- (f) “President” means the President of the District Forum or the State Commission, as the case may be;
- (g) “respondent” means the person who answers any memorandum of appeal; and
- (h) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined therein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II

DISTRICT FORUM

3. *Place of sitting of the District Forum.*—The office of the District Forum shall be located at the headquarters of the District and where the State Government decides to establish a single District Forum having jurisdiction over more Districts than one shall notify the place and jurisdiction of the District Forum so established.

4. *Working days and office hours of the District Forum.*—The working days and office hours of the District Forum shall be the same as those of the offices of the State Government.

5. *Seal and emblem.*—The official seal and emblem of the District Forum shall be such as the State Government may specify.

6. *Sitting of the District Forum.*—The sitting of the District Forum, as and when necessary, shall be convened by the President and it may, in the interest of speedy disposal of the complaint, hold its sittings at any place within its jurisdiction.

7. *Staff of the District Forum.*—The State Government shall appoint such staff as may be necessary to assist the District Forum in its day-to-day work and to perform such functions as are assigned to it by the President. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

The terms and conditions of the staff so appointed for this purpose shall be such as may be laid down by the State Government from time to time.

8. Salaries, honorarium and other allowances of the President and the members of the District Forum.—(i) Where the President of the District Forum is sitting Judge of the District Court, he shall enjoy all benefits which he should have enjoyed as sitting Judge of the District Court. Where the President is not a sitting Judge of the District Court, he shall be entitled to the salary payable a District Judge but the pay plus pension of a retired person shall not exceed the last pay drawn by him, if appointed on whole time basis or an honorarium of Rs. 150/-per day if appointed on part-time basis. Other members, if appointed on wholetime basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 1250/-per month or if appointed on part-time basis a consolidated honorarium of Rs. 100/-per day for each sitting.

(ii) The President and the members of the District Forum shall be entitled to travelling and daily allowance on official tours at the same rates as are admissible to the highest Grade I Officer of the State Government.

(iii) The honorarium or the salary, as the case may be, and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

9. Terms and conditions of services of the President and members of the District Forum.—(i) Before appointment, the President and members of the District Forum shall have to give an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such president or a member, as the case may be.

(ii) The terms and conditions of the service of the President and the members shall not be varied to their dis-advantage during their tenure of office.

(iii) A casual vacancy caused by resignation or removal of the President or any other member of the District Forum shall be filled by fresh appointment.

(iv) No act or proceedings of the District Forum shall be invalid by reasons only of the existence of any vacancy amongst its President or members or any defect in the constitution thereof.

(v) In case of difference of opinion among the members of the District Forum, the majority opinion shall prevail and the opinion or orders of the District Forum shall be expressed in terms of the views of the majority.

(vi) The President or any member ceasing to hold office, as such, shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organisation which has been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

10. Removal of President or members of the District Forum from Office in certain circumstances.—The State Government may remove any person from the office of the President or the member, as the case may be, who,—

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such President or member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such President or member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;

Provided that the President or any member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of this rule except on an enquiry held by the State Government

in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and find the President or the member, as the case may be, guilty, on such grounds.

11. *Procedure on receipt of complaint.*—(1) Where the opposite party admits the allegations made by the complainant, the District Forum shall decide the complaint on merits of the case and the documents presented to it.

(2) If during the proceedings conducted under section 13, the District Forum fixes a date for hearing of the parties, it shall be obligatory on the complainant and the opposite party or their authorised agents to appear before the District Forum on such date of hearing or any other date to which hearing is adjourned. Where the complainant or his authorised agent fails to appear before the District Forum on such day, the District Forum may, in its discretion, either dismiss the complaint for default or decide it on merits. Where the opposite party or its authorised agent fails to appear on the day of hearing, the District Forum may decide the complaint *ex parte*.

(3) While proceeding under sub-rule (2), the District Forum may, on such terms as it may think fit, at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint but the complaint shall be decided as far as possible within a period of three months from the date of notice received by the opposite party where complaint does not require analysis or testing and within five months if it requires analysis or testing of the goods.

(4) Orders of the District Forum shall be duly signed, sealed and dated by the members of the District Forum constituting the Bench and shall be communicated to the parties free of cost.

12. *Procedure to be adopted for analysis and testing of goods.*—(1) Under clause (c) of sub-section (1) of section 13 of the Act, if considered necessary, the District Forum may direct the complainant to provide more than one sample of the goods in clean containers with stopper properly fixed on them.

(2) On receiving the sample of such goods, the District Forum, shall seal it on fix labels on the containers carrying following information:—

- (i) name and address of the appropriate laboratory to whom sample will be sent for analysis and test;
- (ii) name and address of the District Forum;
- (iii) case number; and
- (iv) Seal of the District Forum.

(3) The sample will be sent to the appropriate laboratory by the District Forum for sending report within 45 days or within such extended time as may be granted by the District Forum after specifying the nature of the defect alleged and date of submission of the report.

PART-III

STATE COMMISSION

13. *Salary, honorarium and other allowances of the President and members of the State Commission.*—(1) Where the President of the State Commission is a sitting Judge of the High Court, he all enjoy all the benefits which he should have enjoyed as sitting Judge of the High Court. Where the President is not a sitting Judge of the High Court, he shall receive a consolidated honorarium of Rs. 7,000/- per month, if appointed on wholetime basis or last pay drawn by him minus pension granted to him or an honorarium of Rs. 300/- per day if appointed on part time basis. Her members, if appointed on wholetime basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 1,500/- per month or if appointed on part-time basis a consolidated honorarium of Rs. 250/- per day for the sitting;

Provided that a member shall be eligible to any pension granted to him by the Government or any authority but honorarium plus pension shall not exceed the last pay drawn.

(2) The President and the members shall also be entitled to semi-furnished accommodation.

(3) The President and the members shall be entitled to travelling and daily allowance on official tours at the same rates as are admissible to the highest Grade-I Officer of the State Government.

(4) The honorarium or the salary, as the case may be, and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

14. Terms and conditions of service of the President and members of the State Commission.—

(1) Before appointment, the President and a member of the State Commission shall have to give an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such President or member, as the case may be.

(2) The President and the members shall hold the office for a term of two years and shall not be eligible for re-appointment:

Provided that no President or a member shall hold office as such for a term exceeding 5 years or after he has attained the age of 65 years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the President or a member may:—

- (a) by writing under his hand and addresser to the State Government resign his office at any time; and
- (b) be removed from his office in accordance with the provision of rule 15 of these rules.

(4) The terms and conditions of service of the President and the members shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(5) A casual vacancy caused by resignation or removal of the President or any other member of the State Commission under sub-rule (3) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(6) No act or proceedings of the State Commission shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy among its President or members or any defect in the constitution thereof.

(7) In case of difference of opinion among the members of the State Commission, the opinion of the majority shall prevail and the opinion or orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(8) The President or any member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organisation which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

15. Removal of President or members from office in certain circumstances.—(1) The State Government may remove from office, the President or any member who,—

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as the President or member; or

- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the President or a member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the President or any member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of that sub-rule except on an enquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and find the President or any member guilty on such grounds.

16. *Place of siting of the State Commission.*—The office of the State Commission shall be located in the capital of the State.

17. *Working days and office hours of the State Commission.*—The working days and office hours of the State Commission shall be the same as that of the offices of the State Government.

18. *Seal and emblem of the State Commission.*—The official seal and emblem of the State Commission shall be such as the State Government may specify.

19. *Sitting of the State Commission.*—The sitting of the State Commission, as and when necessary, shall be convened by the President and it may, in the interest of speedy disposal of the complaint or appeal, hold its sittings at any place within its jurisdiction.

20. *Staff of the State Commission.*—The State Government shall appoint such staff as may be necessary to assist the State Commission in its day-to-day work and to perform such functions as are assigned to it by the President. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

21. *Procedure to be followed by the State Commission.*—(1) A complaint containing the following particulars shall be presented by the complainant in person or by his agent to the State Commission or be sent by registered post addressed to the State Commission—

- (a) the name, description and the address of the complainant;
- (b) the name, description and address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they can be ascertained;
- (c) the facts relating to complaint and when and where it arose;
- (d) documents in support of the allegations contained in the complaint;
- (e) the relief which the complainant claims.

(2) The State Commission shall, in disposal of any complaint before it, as far as possible, follow the procedure laid down in sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Act in relation to the complaint received by the District Forum.

(3) On the date of hearing or any other date to which the hearing could be adjourned, it shall be obligatory on the parties or their agents to appear before the State Commission. Where the complainant or his agent fails to appear before the State Commission on such days, the State Commission may in its discretion either dismiss the complaint for default or decide it on merits. Where the opposite party or its agent fails to appear on the date of hearing, the State Commission may decide the complaint *ex-parte*.

(4) The State Commission may, on such terms as it deems it and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint but the complaint shall be decided, as far as possible within a period of three months from the date of notice received by the opposite party where the complaint does not require analysis or testing of commodities and within five months if it requires such analysis or testing.

(5) If the proceedings conducted under sub-rule (3), the State Commission is satisfied with the allegations contained in the complaint, it shall issue orders to the opposite party or parties, as the case may be, directing him or them to take one or more of the things mentioned in sub-section (1) of section 14 of the Act.

22. *Procedure of hearing the appeal.*—(1) Memorandum shall be presented by the appellant or his agent to the State Commission in person or be sent by registered post addressed to the Commission.

(2) Every memorandum filed under sub-rule (1) shall be in legible handwriting, preferably typed, and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Each memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order of the District Forum appealed against and such of the documents as may be required to support grounds of objection mentioned in the memorandum.

(4) When the appeal is presented after the expiry of the period of limitation as specified in the Act, the memorandum shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the State Commission that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(5) The appellant shall submit four copies of the memorandum to the Commission for official purpose.

(6) On the date of hearing or on any other day to which the hearing may adjourned, it shall be obligatory for the parties or their agents to appear before the State Commission. If the appellant or his agent fails to appear on such date, the State Commission may in its discretion, either dismiss the appeal or decide it *ex-parte* on merits. If the respondent or his agent fails to appear on such date, the State Commission shall proceed *ex-parte* and shall decide the appeal on merits of the case.

(7) The appellant shall not, except by leave of the State Commission, urge or be heard in support of any ground or objection not set forth in the memorandum but the State Commission, in deciding the appeal, may not confine to the grounds of objection set forth in the memorandum:

Provided that the State Commission shall not rest its decision on any grounds other than those specified in the memorandum unless the party who may be affected thereby, has been given an opportunity of being heard by the State Commission.

(8) The State Commission, on such terms as it may think fit, and at any stage, adjourn the hearing of the appeal, but not more than one adjournment shall ordinarily be given and the appeal should be decided as far as possible within 90 days from the first date of hearing.

(9) The order of the State Commission, on appeal, shall be signed and dated by the members of the State Commission and communicated to the parties free of charge.

By order,
S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary.

